भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 798

दिनांक 07.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

रसायन विनिर्माण में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता संबंधी रणनीतियाँ

798. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में घरेलू विनिर्माण को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने, अग्रणी रसायन विनिर्माण कंपनियों को आगे बढ़ने में सहयोग देने, निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने वाली कार्यनीतियों का अनुसरण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार की गई रणनीति और उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में कुल कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ख) घरेलू विनिर्माण की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, अग्रणी रसायन विनिर्माण कंपनियों के उद्भव को बढ़ावा देने, निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने और देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने निम्नलिखित पहल की हैं:

(i) **पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)**
भारत सरकार ने निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए पीसीपीआईआर नीति अधिसूचित की है। पीसीपीआईआर बड़े पैमाने पर एकीकृत और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बढ़ावा देते हैं। पीसीपीआईआर की संकल्पना एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में की गई है जिसमें व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करने के लिए सामान्य बुनियादी ढाँचा और सहायक सेवाएँ शामिल हैं। वर्तमान में, इन क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), गुजरात (दाहेज) और ओडिशा (पारादीप) राज्यों में तीन पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) कार्यान्वित किए गए हैं।

इन पीसीपीआईआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

संकेतक	गुजरात	आंध्र प्रदेश	ओडिशा	कुल
स्थान/ क्षेत्र	दाहेज, भरूच	विशाखापत्तनम–काकीनाडा	पारादीप	-
अनुमोदन की तारीख	फरवरी, 2009	फरवरी, 2009	दिसम्बर, 2010	-
कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	453.00	640.00	284.15	1377.15
किया गया निवेश (रूपये करोड़ में)	1,28,509	58,918	73,518	2,60,945
सृजित रोज़गार (सं.)	2,45,140	86,123	40,000	3,71,263
रासायनिक इकाइयों की संख्या	626	150	48	824

इन पीसीपीआईआर ने 2.6 लाख करोड़ रुपये का संचयी निवेश आकर्षित किया है और इसके परिणामस्वरूप 824 इकाइयां स्थापित हुईं तथा 3,71,263 व्यक्तियों को रोजगार मिला।

(ii) प्लास्टिक पार्क योजना

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए योजना को क्रियान्वित करता है। यह योजना आवश्यक अत्याधुनिक अवसंरचना और सक्षम सामान्य सुविधाओं के साथ आवश्यकता-आधारित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करना है ताकि इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजित करने में सहायता मिल सके। इस योजना के तहत, भारत सरकार परियोजना लागत के 50% तक अनुदान निधि प्रदान करती है, जो प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब तक 10 प्लास्टिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं और ये कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(iii) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (पीडब्लूएमसी):

क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने के विभाग के प्रयासों के एक भाग के रूप में, विभाग ने बेंगलुरु, भागलपुर और वाराणसी में पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना की है।

(iv) उत्कृष्टता केंद्र (सीओई):

रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में नए मोलेक्यूल और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए

अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विभाग ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। इसका उद्देश्य मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार करने और पॉलिमर, रसायन और प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करना है। इस योजना का जोर मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार पर है। इस योजना के तहत, भारत सरकार कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत अब तक, 18 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(v) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):

रसायन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से, कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर, इस क्षेत्र में 100% एफडीआई को स्वचालित रूप से अनुमति देने की नीति है। पिछले 5 वर्षों में, इस क्षेत्र में 42,641 करोड़ रुपये का एफडीआई आया है।

(vi) कौशल:

केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अंतर्गत एक तकनीकी शिक्षा संस्थान है, जो देश में पेट्रोरसायन और संबद्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता के साथ-साथ शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है। सिपेट के देश भर में 47 केंद्र हैं, जिनमें 8 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीटी), 32 कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र (सीएसटीएस), पॉलिमर में उन्नत अनुसंधान के लिए 3 स्कूल (एसएआरपी) और 4 उप-केंद्र शामिल हैं। 2023-24 के दौरान, सिपेट ने 66,606 व्यक्तियों (5,046 दीर्घकालिक व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम और 61,560 अल्पकालिक व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम) को प्रशिक्षण प्रदान किया।

(vii) गुणवत्ता नियंत्रण आदेश :

आयातित या घरेलू स्तर पर उत्पादित रसायनों और पेट्रोरसायनों में ऐसी अशुद्धियाँ हो सकती हैं जो मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए, देश में उत्पादित रसायनों/पेट्रोरसायनों की गुणवत्ता में सुधार करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है कि केवल गुणवत्ता वाले रसायनों का ही आयात किया जाए। इस उद्देश्य से, विभाग ने रसायनों/पेट्रोरसायनों के मानकों को अनिवार्य बनाने का कार्य शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातक और घरेलू विनिर्माता, दोनों ही भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के गुणवत्ता मापदंडों को पूरा करते हैं। ऐसे रसायन/पेट्रोरसायन बीआईएस से प्राप्त लाइसेंस के तहत मानक चिह्न धारण करेंगे। यह तंत्र इन उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है।

(viii) संवर्धन कार्यक्रम:

रसायन संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस) के अंतर्गत, विभाग निवेश आकर्षित करने, उद्योग जगत के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने तथा व्यवसाय से व्यवसाय के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकायों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करता है।

(ग) अब तक स्वीकृत 18 उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) में से 3 सीओई महाराष्ट्र में स्थापित किए गए हैं। सीओई का विवरण नीचे दिया गया है:-

संख्या	उत्कृष्टता केंद्र का स्थान (सीओई)	शीर्षक	अनुमोदन की तारीख	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान (करोड़ रु.)	स्वीकृत राशि (करोड़ रूपये में)
1.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	सस्टेनेबल पॉलीमर उद्योग से अनुसंधान एंव नवाचार तक	अप्रैल, 2011	6.00	6.00
2.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	कस्टेमाइज्ड एडीटिव मैन्यूफैक्चरिंग के लिए स्पेशलिटी पॉलिमर	फरवरी, 2019	2.80	1.40
3.	भारतीय रबर पदार्थ अनुसंधान संस्थान, पुणे	रबर और संबद्ध तैयार उत्पादों के मूल्यवर्धित खिलौनों का डिज़ाइन और विकास	फरवरी, 2022	4.93	2.50

इसके अतिरिक्त, विभाग ने औरंगाबाद और चंद्रपुर में कौशल और तकनीकी सहायता (सीएसटीएस) के लिए केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) के दो केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र शैक्षणिक, कौशल विकास और तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करके क्षेत्र में पेट्रोरसायन और संबद्ध उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

महाराष्ट्र में रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस) के तहत, रसायन एंव पेट्रोरसायन विभाग ने फिक्की के साथ संयुक्त रूप से बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में 17 से 19 अक्टूबर 2024 के दौरान द्विवार्षिक कार्यक्रम “इंडिया केम 2024” के 13वें संस्करण का आयोजन किया जिसका विषय था - "एडवांटेज भारत: इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पेविंग द फ्यूचर”। इंडिया केम एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। यह आयोजन अन्य बातों के साथ-साथ

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। यह आयोजन एक सम्मेलन सह प्रदर्शनी है और इसमें वैश्विक और घरेलू उद्योग, प्रदर्शक, राज्य सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल व्यापक रूप से भाग लेते हैं। इस आयोजन में 49 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों सहित 172 प्रदर्शकों ने भाग लिया और 78 वैश्विक सीईओ, 135 वक्ता और 689 विदेशी प्रतिभागियों ने भाग लिया। इंडिया केम 2024 में कुल 1,115 भारतीय प्रतिनिधियों और 8,720 व्यापारिक आगंतुकों ने भाग लिया।

*****